वित्तीय वर्ष 2012–2013 के बजट अनुमानों पर माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2012–2013 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

मान्यवर, यह मेरा परम सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इस सम्मानित सदन के समक्ष मुझे वित्तीय वर्ष 2012–2013 का बजट प्रस्तुत करने का अवसर दिया है । प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास व्यक्त करते हुए अपार जन–समर्थन देकर इस सरकार को चुना है । जनता की इस सरकार से बड़ी अपेक्षायें हैं ।

विगत पाँच वर्षों में इस प्रदेश की जो दुर्गति हुई है उससे न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर हुई है अपितु हमारे सामाजिक ताने–बाने पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ा है । इस दौरान भ्रष्टाचार, लूट–खसोट, धांधली व निर्दोष लोगों के उत्पीड़न का कीर्तिमान स्थापित हुआ । समाजवादी सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी विकास व जन–कल्याण की लगभग सभी

योजनाओं को वर्ष 2007 में बन्द कर दिया गया । जनता की गाढ़ी कमाई को अस्पतालों, शिक्षण संस्थाओं, सामाजिक उत्थान की योजनाओं, ग्रामीण विकास, अवस्थापना सुविधाओं आदि के स्थान पर पत्थर, मूर्तियों और स्मारकों पर लगा दिया गया । प्रशासन दिशाहीन हो गया और उसका मनोबल लगातार टूटता चला गया । प्रदेश भ्रष्टाचार, निरंकुश राजतंत्र, अलोकतांत्रिक परम्पराओं और अवनति के गहरे गड्ढे में धकेल दिया गया ।

माननीय अध्यक्ष जी, विरासत में हमें जर्जर अर्थव्यवस्था, टुकड़ों में बँटा समाज, सभी कीर्तिमान तोड़ता हुआ भ्रष्ट तंत्र, बिगड़ी कानून व्यवस्था और हताश–निराश प्रशासनिक तंत्र मिला है । विगत वर्षों में जनता की सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति मानकर व सभी नियमों को ताक पर रखकर उसका मनमाना उपयोग किया गया । एक ऐसा निरंकुश प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया गया जिसमें सिर्फ चापलूसों और भ्रष्टाचारियों का एकछत्र राज था ।

प्रदेश की जनता ने इस दौरान प्रजातंत्र पर कुठाराघात का दुःखदायी नजारा देखा है । लोकतांत्रिक गतिविधियों को बर्बरतापूर्वक कुचल दिया गया । शान्तिपूर्ण व अहिंसक प्रतिरोध तक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गयी । भय एवं आतंक का माहौल पूरे पाँच वर्ष प्रदेश में बना रहा । समाजवादी सोच इस दिशा

की ओर पूर्णतः समर्पित है कि सामाजिक विकास कुछ हाथों में सत्ता व ताकत से नहीं वरन् लोकतंत्र के सशक्तिकरण के माध्यम से होता है । इसी विश्वास के साथ हमारी सरकार पुनः सबकी आवाज को स्थान देने व कानून के राज को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है ।

मान्यवर, समाजवादी सरकार की मान्यता है कि सार्वजनिक निधि के ऊपर इस सम्मानित सदन का अधिकार होता है । निधि के स्वामी की अनुमति से प्रदेश के खजाने को प्रदेश के विकास कार्यों पर खर्च करने का हमारा व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के मान्य सिद्धान्तों को मजबूत बनाने वाला है ।

एक ऐतिहासिक जनादेश के माध्यम से जनाकांक्षाओं को पूरा करने का जो पुनीत दायित्व हमें मिला है, हम उसे पूरी ईमानदारी के साथ इस सदन के सहयोग व मार्गदर्शन से पूरा करने का प्रयास करेंगे ।

माननीय नेताजी, तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने वर्ष 1990–91 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि “हम बख्शीश की राजनीति के स्थान पर व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति चाहते हैं । हम समाज के हर वर्ग को इतना शक्तिशाली और समृद्ध बनाने तथा ऐसी चेतना से

सम्पन्न करना चाहते हैं कि उसमें अपने उत्थान के लिए स्वयं सामर्थ्य पैदा हो । इसी उद्देश्य को लेकर हम राजनीति में आये हैं । हमारी राजनीति का आधार सिद्धान्तों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं से निर्मित हुआ है । सत्ता हमारे लिए जनता की सेवा का सशक्त माध्यम है ।"

उत्तर प्रदेश जो कभी विकास में देश का अग्रणी प्रदेश हुआ करता था, विगत पाँच वर्षों में अन्य प्रदेशों की तुलना में काफी पीछे छूट गया है, हमें इसे पुनः विकास के पथ पर नई सोच के साथ तीव्र गति से आगे ले जाना है । हमने युवा पीढ़ी व नौजवानों पर विशेष ध्यान देने का संकल्प किया है । प्रदेश के नौजवानों में प्रदेश को तीव्र गति से आगे ले जाने की क्षमता है। इस क्षमता का भरपूर उपयोग हमारी सरकार द्वारा किया जायेगा ।

मान्यवर, विगत दो माह में ही प्रदेश की जनता को सकारात्मक परिवर्तन की अनुभूति हुई है । निरंकुश शासन की जगह पारदर्शी व जबावदेह शासन, भ्रष्ट और संवेदनहीन प्रशासनिक व्यवस्था की जगह ईमानदार एवं संवेदनशील प्रशासन तथा सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण एवं सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धताओं के साथ हम आगे बढ़े हैं । हमें एक ऐसा सम्पन्न एवं शक्तिशाली प्रदेश बनाना है, जिसमें विकास की गति त्वरित एवं निर्बाध हो तथा जिसमें सभी वर्गों की

भागीदारी हो । हमारा लक्ष्य गरीब व असहाय लोगों तथा किसानों के चेहरे पर मुस्कराहट लाना है । हम ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, जिसमें प्रशासनिक मनोबल वापस आये तथा उसकी क्षमता में वृद्धि हो और प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ–साथ उत्तरोत्तर प्रगति हो ।

मान्यवर, विधान सभा चुनावों के पूर्व हमने प्रदेश की जनता से समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई के लिये और प्रदेश के समग्र विकास हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को चलाये जाने का वायदा किया था । यह जानकर आपको खुशी होगी कि जनकल्याण और विकास की हमारी प्रतिबद्धताओं को मूर्तरूप देने के लिये और इन वायदों को पूरा करने के लिये प्रस्तुत बजट में कई योजनायें सम्मिलित की गई हैं ।

शपथ ग्रहण करने के पश्चात् सबसे पहले हमारी समाजवादी सरकार ने चुनावी घोषणा–पत्र पर अमल करते हुये बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना पारित की जो अब बजट व्यवस्था के साथ अमल में लायी जायेगी । इसमें बेरोजगार युवाओं को एक हजार रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा । इसके लिये हमने अपने बजट में 1,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है । कक्षा 10वीं एवं 12वीं पास विद्यार्थियों को टैबलेट एवं लैपटॉप दिये जाने की योजना भी बन रही है । शीघ्र ही छात्रों को इनका

वितरण प्रारम्भ हो जायेगा जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसरों की शुरूआत होगी । जब गाँव–गाँव में लैपटॉप एवं टैबलेट पहुँचेंगे तो गाँव के विद्यार्थियों में कम्प्यूटर का डर दूर हो जायेगा तथा गाँव में रहने वाले तथा गरीब घर के बच्चों को भी रोजगार एवं तरक्की के वो अवसर मिल सकेंगे जो अभी केवल शहर में रहने वाले साधन सम्पन्न वर्ग के बच्चों को ही मिल पाते हैं । बजट में इसके लिये हमने 2,721.24 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है । पिछली समाजवादी सरकार ने छात्राओं के लिये कन्या विद्या धन योजना लागू की थी जिसे पिछली सरकार ने बन्द कर दिया था । इस योजना को पुनः चालू करके प्रदेश की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित किया जायेगा और इसके लिये हमने 446.35 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ।

मान्यवर, आपको याद होगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में कृषक दुर्घटना बीमा योजना की शुरूआत की थी । हमारी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा–पत्र के एक और वायदे को पूरा करते हुये किसानों के हित के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर पाँच लाख रुपये कर दी है जिसके लिये हमने 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की है ।

हमारी सरकार की रणनीति का एक पहलू यह भी होगा कि प्रदेश में आर्थिक विकास का एक ऐसा वातावरण तैयार हो जिससे पूँजी निवेशकों का सरकार की नीतियों में विश्वास बढ़े और अधिकाधिक निजी पूँजी निवेशकों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें ।

मान्यवर, अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2012–2013 की संक्षिप्त रूपरेखा सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूँगा ।

- इस सम्मानित सदन को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार द्वारा 2012–2013 के लिये प्रस्तुत बजट का आकार दो लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रुपये (2,00,110.61 करोड़ रुपये) है जो अब तक प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्तावों में सबसे अधिक है तथा गत वर्ष 2011–2012 के बजट के सापेक्ष 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य का बजट दो लाख करोड़ की सीमा पार कर रहा है ।

- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें अपने स्वयं के कर राजस्व में गत वर्ष की अपेक्षा 22 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है ।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राज्य के चहुँमुखी विकास एवं प्राथमिकताओं को पूर्ण करने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी ।

- वर्ष 2012–2013 बारहवीं योजना (2012–2017) का प्रथम वर्ष है । इस दृष्टि से वर्ष 2012–2013 के बजट में 13,650.36 करोड़ रुपये की 280 नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं ।

- अवस्थापना सुविधाओं यथा सड़क, सेतु, सिंचाई एवं ऊर्जा के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिये 23,591.72 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष से 7 प्रतिशत अधिक है । मुख्य रूप से बिजली की नई योजनाओं के लिये 585.69 करोड़ रुपये, शहरी विकास की नई योजनाओं के लिये 473.92 करोड़ रुपये, त्वरित आर्थिक विकास के लिये 500 करोड़ रुपये, सड़कों और सेतुओं के निर्माण की नई योजनाओं के लिये 2,489.03 करोड़ रुपये तथा सिंचाई की नई योजनाओं के लिये 740.36 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

- कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये 5,432.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

- शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये 33,263.39 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 20 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 17 प्रतिशत है ।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार हेतु बजट 2012–2013 में 7,033.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष की व्यवस्था से 21 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 3.7 प्रतिशत है ।
- समाज कल्याण की योजनाओं के लिये 14,950.62 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गत वर्ष से 14.6 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 7.9 प्रतिशत है ।

वर्ष 2012–2013 में प्रारम्भ किये जाने वाले मुख्य कार्यक्रम

माननीय अध्यक्ष जी,

मैंने अभी कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया है परन्तु अपनी सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बजट में सम्मिलित कुछ प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का मैं उल्लेख करना चाहूँगा ।

किसानों के लिये योजनायें

- यह सम्मानित सदन किसानों के लिये हमारी प्रतिबद्धता से भली–भाँति अवगत है । किसान दुर्घटना बीमा योजना का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ । किसानों की एक अन्य बड़ी समस्या उन पर बढ़ता कर्ज का बोझ है ।
- किसानों के लिये ऋण राहत योजना बनायी जा रही है । प्रदेश के ऐसे किसानों जिन्होंने अपनी कृषि भूमि को बन्धक रखकर प्रदेश के सहकारी बैंको से कृषि सम्बन्धित कार्यों हेतु एक निश्चित अधिकतम धनराशि तक ऋण लिया है और ऋण अदा न कर पाने के कारण भूमि की नीलामी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, को राहत प्रदान करने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- भूमि सेना योजना को पुनर्जीवित कर चलाये जाने हेतु 47.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । इस योजना के अन्तर्गत ऊसर, बंजर तथा बीहड़ जमीन को खेती योग्य बनाकर भूमिहीन एवं गरीबों को आवंटित किया जायेगा ।
- गन्ना किसानों को अवशेष बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।
- आगामी रबी 2012–2013 हेतु 8 लाख मीट्रिक टन फॉस्फेटिक एवं 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया

खाद के पूर्व भण्डारण की व्यवस्था रहेगी, जिसके लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- वर्ष 2012–2013 में खरीफ हेतु 15.42 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । वर्ष 2012–2013 में खरीफ हेतु 17.30 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है। इसके लिये 137.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- हमारी सरकार किसानों के हित में उनकी भूमि के अधिग्रहण के संबंध में अपने चुनाव घोषणा–पत्र के अनुरूप शीघ्र ही एक नई भूमि अधिग्रहण नीति भी लेकर आयेगी जिससे व्याप्त विसंगतियों का समाधान होगा और किसानों को राहत महसूस होगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये योजनायें

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं है । हमने इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाये हैं ।

- डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

  प्रदेश के चयनित पिछड़े राजस्व ग्रामों के चहुँमुखी विकास हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया

समग्र ग्राम विकास योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

योजना के अन्तर्गत 36 विकास कार्यक्रमों से पाँच वर्षों में लगभग 10,000 ग्रामों को विकसित किये जाने का लक्ष्य है । प्रथम चरण (2012–2013) में लगभग 1600 ग्राम लिये जायेगें । प्रत्येक जनपद हेतु ग्रामों की संख्या का निर्धारण पिछड़ेपन सूचकांक के आधार पर किया जायेगा ।

- डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप योजना

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अन्तर्गत 748 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण एवं डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है । इस योजना हेतु 300.08 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- लोहिया ग्रामीण आवास योजना

    हमारी सरकार द्वारा "लोहिया ग्रामीण आवास योजना" प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- ग्रामीण विद्युत फीडर

    ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय एवं कृषि उपयोग के लिये विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु पृथक विद्युत फीडर की स्थापना के लिये यथोचित राज्यांश की व्यवस्था की जा रही है ।

- सौर ऊर्जा

    सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन परियोजनायें स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक निजी निवेश आकर्षित किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे । सौर विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कमजोर वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनायें

समाजवादी सरकार समाज के सभी कमजोर वर्गो के लिए उन्नति के अवसर खोलने के लिए कृत् संकल्प

है । हमने इस दिशा में बजट के माध्यम से कई कदम उठाये हैं ।

- प्रदेश के सभी बी0पी0एल0 परिवारों की महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजन को एक–एक कम्बल दिये जाने के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

- रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे गरीब परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं परन्तु उन्हें बी0पी0एल0 योजना / अन्त्योदय योजना या किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है । योजनान्तर्गत 400 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से पेंशन दिये जाने का प्रावधान है । योजना हेतु 1,111.85 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिये 2,074.11 करोड़ रुपये की योजनायें बजट में प्रस्तावित हैं । इसमें मुख्य रूप से प्रदेश के कब्रिस्तानों / अन्त्येष्टि स्थलों पर अवैध कब्जों को रोकने व भूमि की सुरक्षा के लिये चारदीवारी के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से

नीचे के मुस्लिम परिवारों की दसवीं कक्षा पास बालिकाओं को आगे शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह के लिये अनुदान प्रदान किये जाने की योजना 100 करोड़ रुपये के प्रावधान से प्रारम्भ की जा रही है । यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि गरीबी रेखा से नीचे के अन्य वर्गों के परिवारों की कक्षा–10 पास बालिकाओं को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिये भी बजट में योजना प्रस्तावित है ।

- विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 में लगभग 75,000 नये लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है । जिसके लिये 276.91 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
- दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से अक्षम तथा मूकबधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु 407.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

शहरी गरीबों के लिये कल्याणकारी योजनायें

- मेहनतकश शहरी गरीब लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक बेहतरी की अभिनव योजनायें प्रस्तावित हैं । प्रदेश के रिक्शा चालकों को मोटर / बैटरी

/ सौर ऊर्जा चालित अत्याधुनिक रिक्शे दिये जाने की योजना प्रमुख है । इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- शहरी गरीब व्यक्तियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की नयी योजना "आसरा" के अन्तर्गत सामान्य रूप से अल्पसंख्यकों तथा सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लाभार्थी लिये जायेंगें । इस योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

- हमारी सरकार लोकतन्त्र सेनानियों को सम्मान राशि, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा देने हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित कर रही है जो हमारी ही पिछली सरकार द्वारा व्यवस्थित राशि से 8.80 करोड़ रुपये अधिक है ।

युवा वर्ग के लिए योजनायें

- युवा वर्ग हमारी सरकार का केन्द्र बिन्दु है । प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है लेकिन जब तक युवाओं को रोजगार प्राप्त नहीं होता है तब तक उनकी बेहतरी हेतु प्रदेश के 30 से 40 वर्ष

की आयु के युवा बेरोजगारों को लाभान्वित करने के लिये शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की गई है । इस योजना से प्रदेश के लगभग नौ लाख बेराजगार युवक / युवतियाँ लाभान्वित होंगे ।

- प्रदेश में दसवीं कक्षा पास कर ग्यारहवी कक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जाने के लिये 302.39 करोड़ रुपये तथा बारहवीं कक्षा पास कर उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाले छात्र–छात्राओं को लैपटॉप उपलब्ध कराये जाने के लिये 2,418.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

- हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में एक प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ की स्थापना भी की जा रही है जिसके द्वारा विदेशों में कार्य करने वाले प्रदेश के नागरिकों जिसमें ज्यादातर युवा हैं, की विभिन्न समस्याओं का निराकरण कराया जायेगा । इस हेतु समुचित बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कर्मचारियों के लिये

- मैं सम्मानित सदन को यह भी सूचित करना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा वेतन आदि मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि

सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को वेतन एवं बकाया के भुगतान में कठिनाई का सामना न करना पड़े जैसा कि गत वर्ष में कर्मचारियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था । इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 के बजट में 56,089.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2011–2012 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है ।

- सम्मानित सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि कोषागारों से किये जाने वाले भुगतान ई–पेमेन्ट के द्वारा किये जाने का प्रयास किया जायेगा, जिससे भुगतान में पारदर्शिता आयेगी तथा पेंशनरों को अधिक सुविधा होगी ।
- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के इलाज हेतु 5 करोड़ रुपये की रिवॉल्विंग फण्ड योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा ।

सामान्य आर्थिक परिदृश्य

प्रदेश की बारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है जिसमे हमारी सरकार द्वारा 10 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है । बारहवीं पंचवर्षीय योजना

पर निकट भविष्य में केन्द्रीय योजना आयोग के साथ विचार–विमर्श किया जायेगा ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर 6.9 प्रतिशत रही । इतना ही नहीं, देश और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में गैप बढ़कर 50 प्रतिशत से अधिक हो गया । अवस्थापना सुविधाओं के अभाव के कारण औद्योगीकरण की गति बाधित रही ।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2012–2013 में प्रदेश की योजना का आकार 51,000 करोड़ रुपये रखा गया है जो वर्ष 2011–2012 की तुलना में 4,000 करोड़ रुपये अधिक है ।

विकास की प्राथमिकताओं को मूर्तरूप प्रदान किये जाने हेतु सरकार द्वारा विशेष महत्व के "थ्रस्ट एरियाज" चिन्हित किये गये हैं जिनमें योजनाओं का सतत् प्रभावी अनुश्रवण किया जायेगा । केन्द्र पुरोनिधारित योजनाओं की गहन समीक्षा की जायेगी ताकि इनका सही क्रियान्वयन हो सके तथा केन्द्र सरकार से समय से तथा अधिकतम धनराशि प्राप्त हो सके ।

प्रदेश में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे । इस क्रम में विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड पैकेज हेतु 900.33 करोड़ रुपये, प्रदेश के त्वरित विकास के लिये 500

करोड़ रुपये, बॉर्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम हेतु 55 करोड़ रुपये तथा "इन्टीग्रेटेड ऐक्शन प्लान" योजना में सम्मिलित कार्यो के लिये 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 291 करोड़ रुपये एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 109 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

मान्यवर,

अब मैं कुछ मुख्य विभागों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बजट प्रस्तावों का उल्लेख करना चाहूँगा ।

कानून व्यवस्था

प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जाना सरकार की प्राथमिकता है ताकि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक भयमुक्त एवं अपराधमुक्त वातावरण में जीवन–यापन कर सके एवं प्रदेश में साम्प्रदायिक तथा जातिगत सौहार्द्र बना रहे । इसके लिये सरकार द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

प्रभावी कानून व्यवस्था लागू करने के लिये पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिये 10,378.20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु तीन महानगरों लखनऊ, वाराणसी एवं कानपुर में महत्वपूर्ण चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी है ।

पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों की आवास की समस्या से हमारी सरकार भलीभाँति अवगत है । अतः पुलिस विभाग के आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–2013 में 417.75 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है ।

उपनिरीक्षक एवं विवेचना अधिकारियों के लिए गौतमबुद्ध नगर में 25 कमरों का एक ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

कृषि

हमारी सरकार की यह स्पष्ट मान्यता है कि देश की तरक्की किसानों की तरक्की के बिना सम्भव नहीं है । इसलिए हमारी सरकार कृषि तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती है ।

कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिये 5,432.37 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वर्तमान खरीफ सत्र 2012 में 182.59 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 1.81 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2,721.26 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ।

संकर मक्का बीज, मूंगफली व गन्ने के उन्नतशील बीजों की उपलब्धता के लिये 72.51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

"राष्ट्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मिशन" प्रदेश में इस उद्देश्य से चलाया जा रहा है कि औद्यानिक फसलों की क्षति होने पर किसानों के नुकसान को कम करा जाय ।

पान उत्पादकों को संरक्षण प्रदान किये जाने की योजना प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है ।

प्रदेश के जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान तथा पार्कों की स्थापना हेतु 4.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्राम्य विकास

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के साथ–साथ अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2012–2013 में 80 लाख परिवारों को 4200 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने हेतु राज्यांश के रूप में पर्याप्त प्रावधान किया गया है ।

ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यों हेतु वर्ष 2012–2013 में 41,000 नये हैण्डपम्प, 41,000 रिबोर हैण्डपम्प तथा 800 पाइप वाटर सप्लाई स्कीम चलाया जाना प्रस्तावित है ।

पंचायती राज

पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं के लिए 5,311.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत शौचालय विहीन बी0पी0एल0 परिवारों के लिये शौचालय निर्माण हेतु 51.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

दुग्ध विकास

वर्तमान दुग्ध संघों / समितियों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में नई समितियों का गठन तथा निष्क्रिय समितियों का पुनर्गठन किया जायेगा ।

पाँच लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता का एक डेरी प्लाण्ट जनपद लखनऊ में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पशुधन

प्रदेश के गावों में समग्र पशुपालन विकास के कार्यक्रम चलाये जाने का लक्ष्य है जिसमें चयनित ग्रामों को आधुनिक पशुधन प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा ।

पशु रोग अनुसंधान सेवाओं एवं पशु स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मत्स्य

वित्तीय वर्ष 2012–2013 के अन्त तक मत्स्य उत्पादन का स्तर 4.60 लाख मीट्रिन टन लाये जाने का लक्ष्य है ।

मछुआ समुदाय के समिति के सदस्यों / सक्रिय मत्स्य पालकों को दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित कराया जायेगा ।

मछुआ समुदाय के आवास विहीन 1500 मछुआ परिवारों को 50,000 रुपये प्रति आवास की दर से निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान करायी जायेगी ।

ऊर्जा

प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने तथा आपूर्ति में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है । ऊर्जा क्षेत्र की योजनाओं के लिये 8,225.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पूर्व में स्थापित एवं चालू विद्युत गृहों की विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि हेतु पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण की योजना विकसित की जायेगी ।

बिजली उत्पादन और वितरण योजनाओं के लिये 3,429.48 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश की जनता को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने हेतु विद्युत निगम को क्षतिपूर्ति की मद में 4,040 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है जो वर्ष 2011–2012 की तुलना में 47 प्रतिशत अधिक है ।

राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बुनकरों को राहत प्रदान करने हेतु पॉवरलूम बुनकरों के बकाया बिजली बिलों के एकमुश्त भुगतान हेतु लगभग 127.60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सड़क एवं यातायात

सड़कों के लिये 4,595.68 करोड़ रुपये, सेतुओं के लिये 1,330.10 करोड़ रुपये तथा सम्पर्क मार्गों के लिये 914.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पी0पी0पी0 मोड पर सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश में 1,77,094 किलोमीटर राज्य मार्गों तथा अन्य श्रेणी के मार्गों के अनुरक्षण हेतु 1,854.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

वर्ष 2013 में जनपद इलाहाबाद में कुम्भ मेला के आयोजन हेतु मार्गों के सुधार हेतु लगभग 256 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

ग्रामीण अंचलों में पुलों के निर्माण हेतु 550 करोड़ रुपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 345 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

सिंचाई

सिंचाई कार्यों के लिये 8,525.70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश में कुल 10,510 नहरें हैं । वर्ष 2012–2013 में खरीफ में 9,654 नहरों तथा रबी में 9,850 नहरों के

टेलों पर पानी पहुँचाया जाना प्रस्तावित है जो अब तक सर्वाधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजना हेतु धनराशि 2,517.86 करोड़ रुपये प्रस्तावित है ।

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्यों आदि हेतु 724.75 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बाँधों के सुदृढीकरण एवं नहरों की क्षतिग्रस्त पटरियों को ठीक किये जाने हेतु 1,816.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

नहरों की सिल्ट सफाई कार्य में जनसहभागिता के माध्यम से पारदर्शिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा सिल्ट सफाई का कार्य खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के पूर्व कराया जायेगा ।

लघु सिंचाई

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 1,344.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वित्तीय वर्ष में लगभग 1,40,000 निःशुल्क बोरिंग करायी जायेगी ।

निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत 5,000 मध्यम गहरे नलकूप, 1,000 गहरे नलकूप, 300 सतही

पम्पसेट, 5,479 सामुदायिक ब्लास्ट कूप तथा 539 चेकडैम आदि कार्य प्रस्तावित हैं ।

नगर विकास

नगर विकास की योजनाओं के लिये 5,031 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2011–2012 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है ।

नगरीय स्थानीय निकायों में जनहित से जुड़ी तात्कालिक आवश्यकताओं तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु "नया सवेरा नगर विकास योजना" जिसके लिये 241 करोड़ रुपये के ऋण हेतु बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

आगरा पेयजल पूर्ति परियोजना हेतु 290 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में 17 नगरीय निकायों में पी0पी0पी0 मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र तथा स्लम में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली, जल निकासी एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण की योजना आरम्भ की जा रही है । इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी हेतु वर्ष 2012–2013 में 70 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है ।

नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सेक्टर में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 76 करोड़ रुपये, सीवरेज हेतु 60 करोड़ रुपये, पेयजल के लिये 474.07 करोड़ रुपये तथा जल निकासी के लिये 44.99 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान प्रस्तावित है ।

इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले के लिये 200 करोड़ रुपये की पृथक बजट व्यवस्था की गयी है ।

आवास एवं शहरी नियोजन

आवास एवं शहरी नियोजन के लिये 627.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

लखनऊ की गोमतीनगर विस्तार योजना में शहीद पथ के समानान्तर 137 एकड़ क्षेत्रफल पर पी0पी0पी0 मोड पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स काम्पलेक्स विकसित किया जायेगा ।

लखनऊ में 500 एकड़ में जनेश्वर मिश्रा पार्क की स्थापना की जायेगी जो हरियाली से भरपूर होगा । लखनऊ में जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जायगा ।

लखनऊ नगर के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

औद्योगिक विकास

औद्योगिक क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वातावरण सृजित करने के लिए अवस्थापना विकास को मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है । अवस्थापना परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा भागीदार बनाये जाने का लक्ष्य है ।

आगरा से लखनऊ तक 08 लेन एक्सप्रेस कन्ट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण तथा 04 लेन की नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, गाज़ियाबाद को पी0पी0पी0 के अन्तर्गत थ्रस्ट एरिया के तौर पर चिन्हित किया गया है ।

प्रदेश में उद्योगों का त्वरित विकास करने तथा पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिये नई औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र नीति, 2012 तैयार कर प्रभावी रूप से कार्यान्वित की जायेगी ।

सूचना प्रौद्योगिकी

हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये कृत् संकल्प है । सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित कर इस क्षेत्र में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की जायेगी ।

इस क्षेत्र में अधिक से अधिक पूँजी निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिये सभी स्टेक होल्डर्स के समन्वय से नई सूचना नीति, 2012 लागू की जायेगी ।

राज्य में ई–गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, स्टेट डाटा सेन्टर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को शासकीय एवं अन्य सेवायें निजी क्षेत्र की सहभागिता से जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराये जाने की योजना है । इसके अतिरिक्त 01 जुलाई 2012 से विभिन्न विभागों की चयनित 26 सेवाओं यथा – राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि के फॉर्म्स स्टेट पोर्टल के जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से जमा किये जा सकेंगे ।

लघु उद्योग

वित्तीय वर्ष 2012–2013 हेतु 50,000 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत चार लाख व्यक्तियों हेतु नये रोजगार के अवसर सृजित होने की सम्भावना है ।

प्रदेश के हस्तशिल्पियों के माल के विपणन की समुचित व्यवस्था किये जाने के लिये हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना प्रस्तावित करते हुये समुचित बजट व्यवस्था की जा रही है ।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा क्षेत्र के बुनकरों के लिये एक नयी आर्थिक पैकेज योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्र्तगत प्राथमिक हथकरघा समितियों, शीर्ष सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत बुनकरों को ऋण मुक्त किये जाने हेतु पचास करोड़ रुपये (50 करोड़ रुपये) की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

लगभग 17,000 बुनकरों को एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा, जिसके लिये 33.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

बेसिक शिक्षा

हमारी सरकार का वायदा है कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । इसके दृष्टिगत बेसिक शिक्षा के लिये 25,109.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो वर्ष 2011–2012 की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है ।

सर्वशिक्षा अभियान के लिये 1,700.01 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था राज्यांश के रूप में की गयी है तथा जहाँ–जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा मापदण्डों में कमी की गई है वहाँ राज्य सरकार द्वारा पूर्ति की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है जैसे कक्षा–8 तक के सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकों व दो यूनीफॉर्मों का निःशुल्क वितरण किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में 3,466 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 421 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने तथा 15,262 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण व 52,834 विद्यालयों की चारदीवारी का निर्माण कराया जाना भी प्रस्तावित है ।

प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था हेतु लगभग 1.70 लाख शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण के उपरान्त नियमित करते हुए समायोजन की कार्यवाही 2014–2015 तक पूर्ण कर ली जायेगी ।

शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं अवशेषों के भुगतान में कोई कठिनाई न आये, इस हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 में 16,367.51 करोड रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है ।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 1.35 करोड़ बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु 1,988.94 करोड़ रुपये राज्यांश की व्यवस्था प्रस्तावित है । योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण की भी व्यापक व्यवस्था की गयी है ।

माध्यमिक शिक्षा

कक्षा–8 के बाद अधिक से अधिक बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखें, के उद्‌देश्य से हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिये 9,612.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में भी माध्यमिक शिक्षा की सुलभता हेतु 449 नवीन राजकीय हाईस्कूलों का संचालन तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में 148 मॉडल स्कूलों की स्थापना की जायेगी तथा मुस्लिम बाहुल्य जिलों में नये शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की जायेगी । 144 बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यांश के रूप में 17.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । 198 उच्चीकृत विद्यालयों के

अधूरे भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 35 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के लिये चालू वित्तीय वर्ष में 2,501.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो वर्ष 2011–2012 की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है ।

प्रदेश के "लो ग्रॉस इनरॉलमेन्ट रेशियो" वाले 36 जनपदों में मॉडल डिग्री कालेज खोले जाने की योजना है । इनमें 23 असेवित विकास खण्ड तथा 5 मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं ।

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा के लिये 476.29 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिक विषयों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं तथा असेवित जनपदों में पॉलीटेक्निक खोलने हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है ।

व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा हेतु 507.05 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

स्किल डेवलपमेन्ट हेतु भारत सरकार से सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के अन्तर्गत अपेक्षित धनराशि का बजट प्रावधान चालू वित्तीय वर्ष 2012–2013 में किया गया है ।

सोनभद्र में एक आई0टी0आई0 तथा 02 स्किल डेवलपमेन्ट सेन्टर की स्थापना किये जाने हेतु 2.65 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चिकित्सा शिक्षा

चिकित्सा शिक्षा हेतु 1,907.01 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान स्थापित किये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों / चिकित्सा संस्थानों / चिकित्सा विश्वविद्यालय में असाध्य रोगों, जैसे कैंसर, हृदय रोग तथा गुर्दा रोग के निःशुल्क इलाज हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रत्येक मण्डल में मेडिकल कालेज की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के लिये हमारी सरकार प्रयासरत है । नये निर्माणाधीन मेडिकल कालेजों व सैफई के पैरामेडिकल संस्थान को शीघ्र चालू कराने का प्रयास

है, जिसके लिये बजट में 249.81 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

एलोपैथी चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु 4,419.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रदेश की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ किया जायेगा ।

जिला चिकित्सालयों में आवश्यक उपकरणों के अभाव को देखते हुये सी0टी0 स्कैन मशीन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 115 एक्सरे मशीन, 99 अल्ट्रासाउण्ड मशीनों तथा 455 ई0सी0जी0 मशीनों की व्यवस्था हेतु 33 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । इस व्यवस्था से आम जनता को जिला स्तर पर ही चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी ।

67 चिकित्सालयों में स्वतन्त्र विद्युत फीडर की स्थापना हेतु 85 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । इससे चिकित्सालयों में विद्युत की निर्बाध पूर्ति हो सकेगी तथा आपरेशन आदि नियमित हो सकेंगे ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश विगत् कई दशकों से जापानी इन्सेफलाईटिस की बीमारी से पीड़ित है । इस अभिशाप से प्रदेश को मुक्त कराने हेतु मेडिकल कालेज, गोरखपुर एवं प्रभावित जनपदों के जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत चिकित्सा व्यवस्था हेतु तैयार किया जायेगा ।

समाज कल्याण

समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लिये 13,407.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्ति की मद में लगभग 1,232.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वृद्धावस्था / किसान पेंशन हेतु 1,473.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी तथा परिजनों के इलाज हेतु 138 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

अल्पसंख्यक कल्याण

अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिए 2,074.11 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्ष 2011—2012 की तुलना में 81 प्रतिशत अधिक है ।

मदरसा / मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पूर्व दशम कक्षाओं के अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं को वज़ीफा दिये जाने की योजना के अन्तर्गत 342.94 करोड़ रुपये तथा दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र / छात्राओं को वज़ीफा दिये जाने हेतु 130.53 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र / छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिये 36.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत चयनित जनपदों में निर्माण की विभिन्न योजनाओं हेतु 480.44 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु बजट में 1,619.80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो गत वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं को पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना हेतु 743.44 करोड़ रुपये, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 332.17 करोड़ रुपये और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना हेतु 413.17 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पिछड़े वर्ग के निर्धन लोगों की बीमारी तथा उनकी पुत्रियों की शादी हेतु 90.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश सरकार गर्भवती, धात्री महिलाओं एवं छोटे बच्चों को कुपोषण से बचाने एवं उनके समन्वित विकास के लिये वचनबद्ध है ।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये तथा सहायिकाओं का मानदेय 750 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये मासिक कर दिया गया है जिससे 3.5 लाख कर्मी लाभान्वित होंगे ।

प्रदेश सरकार द्वारा नये आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

"स्वाधार गृह योजना" के नाम से नई योजना संचालित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

खेल एवं युवा कल्याण

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में क्रीड़ा और खेल मैदानों के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा असेवित जनपदों में स्टेडियम के निर्माण हेतु 43.33 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के विस्तार तथा लखनऊ के के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम के जीर्णोधार हेतु 3.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

राजस्व

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में प्रदेश के मण्डल / जनपद / तहसीलों के कार्यों हेतु 124.77 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

प्रत्येक वर्ष प्रदेश में तीव्र बाढ़ आने से गाँव के गाँव बह जाते रहे हैं । इस समस्या के निराकरण के लिये विगत पाँच वर्षों में कोई प्रयास नहीं किया गया । पहली बार हमारी सरकार ने इस दिशा में सार्थक कार्यवाही करते हुये तीव्र बाढ़ से बह जाने वाले ग्रामों के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बनाई है । इस हेतु भूमि क्रय के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है ।

न्याय

जनपदीय न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 में रुपये 362.52 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को 40 करोड़ रुपये की धनराशि दिये जाने हेतु व्यवस्था प्रस्तावित है ।

वन

उत्तर प्रदेश विभिन्न प्रकार के वनों, वन्य जीवों एवं जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है । वन्य जीव संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । जनपद इटावा में शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क विकसित किया जायेगा । इसके लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पक्षी विहारों तथा पार्कों के विकास, ईको पर्यटन विकास तथा फॉरेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के लिये 9 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पर्यटन

प्रदेश के ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों एवं स्थानीय महत्व के पर्यटन स्थलों के विकास के लिये 98.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

संस्कृति

प्रदेश के उन कलाकारों को जिन्होंने अपनी प्रतिभा एवं उत्कृष्ट योगदान द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, उन्हें "यश भारती" सम्मान से पुरस्कृत किये जाने के लिये हमारी सरकार ने सम्मान राशि पाँच लाख से बढ़ाकर ग्यारह लाख प्रति कलाकार कर दी है ।

प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों को सुरक्षित रखने, नृत्य कला जो हमारी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है को संरक्षित करने हेतु 6.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।

पर्यावरण

अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है । इस जिम्मेवारी को पूर्ण करने हेतु समाजवादी सरकार द्वारा पूर्ण प्रयास किए जायेंगे ।

राजकोषीय सेवायें

राज्य के स्वयं के कर राजस्व की प्राप्ति में राजकोषीय सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान है । इनके माध्यम से वाणिज्य कर, आबकारी शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन एवं यात्री कर, मनोरंजन कर, भू–राजस्व आदि की वसूली होती है । वर्ष

2012–2013 के बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व से 62,057.06 करोड़ रुपये की प्राप्तियाँ अनुमानित हैं जो वर्ष 2011–2012 की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2012–2013 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2012–2013 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2012–2013 में एक लाख चौरानवे हजार तीन सौ सत्ताइस करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये (1,94,327.28 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं ।
- कुल प्राप्तियों में एक लाख अट्ठावन हजार आठ सौ सैंतालीस करोड़ छियानवे लाख रुपये (1,58,847.96 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा पैंतीस हजार चार सौ उनासी करोड़ बत्तीस लाख रुपये (35,479.32 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।

- वर्ष 2012–2013 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख इक्कीस हजार पाँच सौ पचासी करोड़ चालीस लाख रुपये (1,21,585.40 करोड़ रुपये) है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश उनसठ हजार पाँच सौ अट्ठाइस करोड़ चौंतीस लाख रुपये (59,528.34 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- वर्ष 2012–2013 में कुल व्यय दो लाख एक सौ दस करोड़ इकसठ लाख रुपये (2,00,110.61 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में एक लाख बावन हजार नौ सौ तिरसठ करोड़ इकसठ लाख रुपये (1,52,963.61 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा सैंतालीस हजार एक सौ सैंतालीस करोड़ रुपये (47,147 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।
- वर्ष 2012–2013 के बजट में छप्पन हजार एक सौ दस करोड़ चौदह लाख रुपये (56,110.14 करोड़ रुपये) आयोजनागत व्यय अनुमानित है ।

राजस्व बचत

- वर्ष 2012–2013 में पाँच हजार आठ सौ चौरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये (5,884.35 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है ।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2012–2013 में इक्कीस हजार पाँच सौ सत्तर करोड़ छब्बीस लाख रुपये (21,570.26 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् वर्ष 2012–2013 में घाटा पाँच हजार सात सौ तिरासी करोड़ तैंतीस लाख रुपये (5,783.33 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।

लोक लेखे से समायोजन

वर्ष 2012–2013 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिये दो हजार पाँच सौ दस करोड़ रुपये (2,510 करोड़ रुपये) लोक लेखे से समायोजित किये जायेंगे ।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2012–2013 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम तीन हजार तीन सौ तेइस करोड़ तैंतीस लाख रुपये (3,323.33 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2012–2013 में प्रारम्भिक शेष तेरह हजार पाँच सौ सात करोड़ सत्तानवे लाख रुपये (13,507.97 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष दस हजार एक सौ चौरासी करोड़ चौंसठ लाख रुपये (10,184.64 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है ।

हमारी सरकार महात्मा गाँधी, डॉ0 राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह जैसे महान नेताओं के सेवा, सादगी और ईमानदारी के शाश्वत सिद्धान्तों के आधार पर काम कर रही है। श्रद्धेय लोहिया जी कहते थे कि "बाकी सरकारें बोली से काम चलाती हैं, हमारी सरकार काम से बोलेगी । हमारी सरकार तरक्की के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बहवूदी में विश्वास करती है । हमारी नीति और कार्यक्रम का अभीष्ट समाज का अन्तिम व्यक्ति है ।"

हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और महानायकों द्वारा एक ऐसे भारत की परिकल्पना की गयी थी, जहाँ सबको विकास के समान व पूरे अवसर मिलें, संसाधनों पर सबका बराबर का हक हो, सबको समान व सुलभ शिक्षा मिले, हर एक को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हों और जहाँ कोई बेरोजगार न हो । इसको साकार करने की विनम्र कोशिश निश्चय ही हमारे बजट में दिखाई देगी । हम समाज और विकास की अन्तिम सीढ़ी पर खड़े आदमी का जीवन स्तर ऊँचा उठाते हुए सर्वांगीण विकास का एक ऐसा अध्याय लिखना चाहते हैं, जो पर्यावरण–हितैषी भी हो । हम आधुनिक तकनीक व प्रदेश की युवा ऊर्जा का रचनात्मक उपयोग करते हुए जनांकाक्षाओं को पूरा करने का हर सम्भव प्रयास करेंगे ।

मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस सम्मानित सदन के माननीय विद्वान सदस्य, चाहे वे किसी भी दल से सम्बन्ध क्यों न रखते हों, प्रदेश के समग्र विकास की इस पहल में हमारा सहयोग करें । प्रदेश की जनता ने अपने हित रक्षार्थ ही हमें चुनकर यहाँ भेजा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी माननीय सदस्यगण जनता के उस विश्वास की रक्षा करेंगे, जो उसने हमारे ऊपर व्यक्त किया है ।

मान्यवर, मैं मंत्रि–परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं

परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त सुश्री वृन्दा सरूप और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ ।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2012–2013 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

ज्येष्ठ 11, शक संवत् 1934,
तदनुसार,
दिनाँक : 01 जून, 2012